



Daily करेंट अफेयर्स

» 26 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. अमित शाह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया।



24 जुलाई 2025 को, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का आधिकारिक शुभारंभ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति द्वारा विकसित यह नीति भारत के सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण और "सहकार से समृद्धि" तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए 20 वर्षीय रोडमैप (2025-45) निर्धारित करती है।

- नई नीति 2002 में तैयार की गई पिछली नीति का स्थान लेती है, और वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और भारत के उभरते आर्थिक परिदृश्य की माँगों को पूरा करने के लिए इसके ढाँचे को अद्यतन करती है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं का कार्यालय करना, उन्हें अधिक समावेशी, पेशेवर, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाना है, जिससे ग्रामीण और शहरी भारत में आजीविका को सहारा मिले।

- अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में 17 बैठकों और चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं में तैयार की गई समिति में सहकारी समितियों, शिक्षाविदों, नाबार्ड, RBI जैसी सरकारी संस्थाओं और राज्य

सरकारों से 648 हितधारकों के सुझाव शामिल किए गए।

- नीति छह रणनीतिक स्तंभों पर जोर देती है: नींव को मजबूत करना; जीवंतता को बढ़ावा देना; भविष्य के व्यवधानों के लिए तैयारी करना; समावेशिता और पहुंच का विस्तार करना; टैक्सी सेवाओं, पर्यटन, बीमा, रियल एस्टेट और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करना; और युवाओं को सहकारी विकास में शामिल करना।

Key Points:-

(i) एक प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करना है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्थापित करना है। राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी सहकारी नीतियों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

(ii) इस शुभारंभ समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM) के प्रमुख भी उपस्थित थे।

(iii) यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह नीति 2034 तक सहकारी क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान को तिगुना कर सकती है, ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर सकती है, और रोजगार, वित्तीय समावेशन और स्थानीय स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बना सकती है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को समतामूलक और सतत विकास के वाहक के रूप में बदलना है।

2. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 166वें आयकर दिवस समारोह की अध्यक्षता की।



25 जुलाई 2025 को, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा आयोजित 166वें आयकर दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में विभाग की मैनुअल प्रक्रियाओं से लेकर AI-संचालित कर प्रशासन तक की यात्रा को मान्यता दी गई, और करदाता सेवाओं एवं स्वैच्छिक अनुपालन में प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया गया।

- समारोह के दौरान, सीतारमण ने उत्कृष्ट आयकर अधिकारियों को उनके दशकों लंबे योगदान के लिए सम्मानित किया - विशेष रूप से मुख्य आयुक्त सुरभि अहलूवालिया, जिन्होंने CBDT के संरचित सोशल मीडिया जुड़ाव का बीड़ा उठाया, और मुख्य आयुक्त अनुराग सहाय, जिन्होंने बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उनके संबोधन में आयकर विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों में परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया - फेसलेस मूल्यांकन और ई-फाइलिंग से लेकर AI एनालिटिक्स तक - जिसे कर दरों में वृद्धि किए बिना उच्चतम कर संग्रह प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है।

- वित्त मंत्री ने विभाग के तीन स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया: रिटर्न प्रसंस्करण, रिफंड जारी करना, और शिकायतों का निवारण - एक ढांचा जिसका उद्देश्य करदाता अनुभव में सुधार करना और कर प्रणाली में विश्वास का निर्माण करना है।

Key Points:-

(i) निर्मला सीतारमण ने CBDT द्वारा शुरू किए गए नज अभियान की सराहना की, जिसे विदेशी संपत्तियों से संबंधित स्वैच्छिक खुलासे को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अभियान को बिना किसी दबाव के अनुपालन बढ़ाने में मिली सफलता के लिए मान्यता मिली।

(ii) इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

(iii) केंद्रीय मंत्री ने पहली बार करदाताओं की सराहना की और बताया कि आकलन वर्ष 2024-25 में 58.57 लाख व्यक्तियों ने पहली बार रिटर्न दाखिल किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिकीकरण और बढ़ी हुई स्वैच्छिक भागीदारी का संकेत है।

3. भारत ने UPI-यूपीयू एकीकरण के माध्यम से वैश्विक आवक प्रेषण को सक्षम करने के लिए DoP-NIPL समझौते पर हस्ताक्षर किए।



भारत के वैश्विक प्रेषण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (DoP) ने 24 जुलाई, 2025 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते (NDA) पर हस्ताक्षर किए।

- इस समझौते का उद्देश्य भारत में आवक धन प्रेषण के लिए एक निर्बाध, सुरक्षित और किफायती चैनल स्थापित करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना है।

- डाक विभाग के उप महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक व्यापार) एल.के. दाश और NIPL के CEO रितेश शुक्ला के बीच NDA का औपचारिक आदान-प्रदान हुआ। यह पहल UPI की वैश्विक पहुँच का विस्तार करने और दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों को किफायती धन प्रेषण सेवाएँ प्रदान करने की भारत की महत्वाकांक्षा में एक मील का पत्थर है।

- यह सहयोग भारत के UPI ढांचे को यूपीयू के इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (IP) के साथ एकीकृत करता है, जिससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों और वैश्विक डाक वित्तीय नेटवर्क के बीच एक द्वि-मार्गी अंतर-संचालनीय नेटवर्क संभव होगा। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीय विश्वसनीय माध्यमों से सुरक्षित और रीयल-टाइम डिजिटल

तरीकों का उपयोग करके भारत में लाभार्थियों को सीधे धन भेज सकेंगे।

Key Points:-

(i) भारत सरकार (GoI) पहले ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, भूटान, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका और सिंगापुर सहित कई देशों में UPI की उपस्थिति का विस्तार कर चुकी है। UPI के विशाल 192-सदस्यीय देश नेटवर्क के शामिल होने से भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सीमा पार वित्तीय समावेशन और भी मजबूत होगा।

(ii) यह साझेदारी UPI-UPU-IP पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्यक्ष एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक बिचौलियों और बैंकिंग शुल्कों को समाप्त करके किफायती धन प्रेषण का वादा करती है। यह धन प्रेषण लेनदेन की लागत को कम करता है और भारतीय श्रमिकों के लिए, विशेष रूप से सीमित बैंकिंग अवसंरचना वाले क्षेत्रों में, पहुँच को बढ़ाता है।

(iii) यह प्रणाली डाक सत्यापन नेटवर्क के साथ मिलकर दो-कारक UPI प्रमाणीकरण का उपयोग करके सुरक्षित और धोखाधड़ी-रोधी लेनदेन भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, इसकी गतिशील संरचना व्यापक पहुँच को सुगम बनाती है, जिससे दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए रीयल-टाइम धन हस्तांतरण प्राप्त करना संभव हो जाता है—इस प्रकार भारत में आने वाले धन प्रेषणों का परिदृश्य बदल जाता है।

4. भारत ने ICF चेन्नई में पहले हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया।



टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत ने 25 जुलाई 2025 को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में अपने पहले हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सफलता का खुलासा किया, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेताओं के बीच भारत के उभरने पर जोर दिया गया।

- हाइड्रोजन से चलने वाला यह कोच, जिसे ड्राइविंग पावर कार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' कार्यक्रम का हिस्सा है। RDSO (रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन) द्वारा डिज़ाइन किया गया यह इंजन 1,200 हॉर्सपावर की शक्ति प्रदान करता है, जो इसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, जो आमतौर पर 500-600 हॉर्सपावर पर चलती हैं।

- डीज़ल इंजनों की तुलना में, हाइड्रोजन ट्रेन शोर के स्तर में 60% की कमी लाती है, जिससे यात्रियों को अधिक शांत और आरामदायक अनुभव मिलता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ—जिसके केवल उप-उत्पाद जल वाष्प और ऊष्मा हैं—यह भारत के अपने रेल नेटवर्क में 2030 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

- भारतीय रेलवे ने 35 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों के विकास के लिए लगभग ₹2,800 करोड़ आवंटित किए हैं, और प्रत्येक रूट पर बुनियादी ढाँचे पर अतिरिक्त ₹70 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग ₹80 करोड़ है। जींद-सोनीपत परीक्षण मार्ग को लक्षित करते हुए, मौजूदा डेमू डिब्बों को हाइड्रोजन ईंधन सेल से सुसज्जित करने के लिए ₹111.83 करोड़ की एक समर्पित पायलट रेट्रोफिट परियोजना चल रही है।

Key Points:-

(i) चेन्नई के सफल परीक्षण के बाद, हरियाणा में जींद-सोनीपत खंड पर परीक्षण चलाने की योजना बनाई गई है, जिसमें 110 किमी/घंटा की अधिकतम गति से लगभग 89 किमी की दूरी तय की जाएगी।

(ii) यह पायलट परियोजना कालका-शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन और नीलगिरि माउंटेन रेलवे जैसे विरासत और पर्वतीय मार्गों पर तैनाती का विस्तार करने से पहले प्रदर्शन मापदंडों और सुरक्षा आवश्यकताओं को ठीक करने में मदद करेगी।

(iii) रेल मंत्री वैष्णव ने ज़ोर देकर कहा कि यह स्वदेशी नवाचार स्थानीय प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग का लाभ उठाता है, जिससे भारत हाइड्रोजन-संचालित रेल प्रणालियों में वैश्विक अग्रदूतों में शुमार हो गया है। यह पहल हरित गतिशीलता, भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा-कुशल सार्वजनिक परिवहन नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।

INTERNATIONAL

1. भारत और मालदीव ने स्मारक डाक टिकट जारी कर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई।



25 जुलाई 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मोदी की माले राजकीय यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए। ये डाक टिकट भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए गए, जो दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता और समुद्री विरासत का प्रतीक हैं।

- स्मारक डाक टिकटों पर दो पारंपरिक समुद्री जहाजों को दर्शाया गया है: भारतीय उरु, जो केरल के ऐतिहासिक बेपोर बोटयार्ड में निर्मित एक विशाल लकड़ी का ढो है, और मालदीव का वधू धोनी, जिसका उपयोग रीफ और तटीय मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। ये जहाज दोनों देशों के बीच सदियों पुराने हिंद महासागर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद औपचारिक रूप से उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। डाक टिकट जारी करने का यह समारोह इस दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि करता है जो राजनीतिक परिवर्तनों और क्षेत्रीय उथल-पुथल के बावजूद जारी रही है।

Key Points:-

(i) यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय राजकीय यात्रा (25-26 जुलाई 2025) का हिस्सा था,

जिसके दौरान दोनों नेताओं ने आठ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता (LoC), मत्स्य पालन में सहयोग, UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान और मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत करने वाली रूपरेखा शामिल थी।

(ii) नरेन्द्र मोदी और मुइज़ू ने भारत द्वारा वित्तपोषित नए रक्षा मंत्रालय मुख्यालय का भी उद्घाटन किया और युवाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनों, प्रवासी सम्मेलनों और भारत के "एक पेड़ माँ के नाम" तथा मालदीव के पांच मिलियन वृक्षारोपण संकल्प के तहत प्रतीकात्मक रूप से आम के पौधे लगाने जैसे समारोहों में भाग लिया।

(iii) राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत-मालदीव संबंधों की प्रशंसा करते हुए उन्हें "लचीला और गहरा" बताया, और मोदी ने भारत की "पड़ोसी पहले" और "विज्ञान महासागर" नीतियों में मालदीव के विशेष स्थान की पुष्टि की। डाक टिकट जारी करने को साझा समुद्री विरासत और आपसी विश्वास से जुड़ा एक सांस्कृतिक संकेत बताया गया।

2. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका 'विभाजनकारी सांस्कृतिक एजेंडे' का हवाला देते हुए दिसंबर 2026 तक UNESCO से बाहर हो जाएगा।



एक प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रम में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने इतिहास में तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) से बाहर निकलने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जुलाई 2025 में इसकी घोषणा की थी, और यह वापसी 31 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस कदम ने वैचारिक विभाजन और शिक्षा एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भविष्य को लेकर वैश्विक चिंताओं को फिर से जगा दिया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने यूनेस्को की नीतियों और कार्यक्रमों के साथ महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए, उन्हें विशेष रूप से "विभाजनकारी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण" करार दिया। प्रशासन ने जोर देकर कहा कि ये कार्यक्रम अब अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता के अनुरूप नहीं हैं।

- वापसी के आधिकारिक कारणों में UNESCO के उन ढाँचों पर आपत्तियाँ शामिल हैं जो विविधता, समानता और समावेश (DEI), नस्लवाद विरोधी पाठ्यक्रम और "पुरुषों में परिवर्तन" जैसी लिंग-केंद्रित पहलों को बढ़ावा देते हैं।

- इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन, LGBTQ+ समावेशन, सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक समानता ढाँचे से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए UNESCO के समर्थन का विरोध किया।

Key Points:-

(i) यह अमेरिका के UNESCO से बाहर निकलने का तीसरा मामला होगा। पहली बार 1984 में राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन के कार्यकाल में इसी तरह के वैचारिक विवादों के कारण ऐसा हुआ था। लगभग दो दशकों के बाद, देश 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के राष्ट्रपति काल में फिर से यूनेस्को में शामिल हुआ। दूसरी बार 2017 में अमेरिका ने UNESCO से बाहर निकलने

का फैसला किया, जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने इज़राइल विरोधी पूर्वाग्रह और फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का हवाला दिया। जुलाई 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका फिर से UNESCO में शामिल हो गया।

(ii) अमेरिका के बाहर निकलने का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वर्तमान में UNESCO के कुल बजट में उसका योगदान 8% से अधिक है। वित्तीय कमी से दुनिया भर में यूनेस्को के शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, इस वापसी से शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को आकार देने में अमेरिका का प्रभाव कम हो जाएगा।

(iii) यह घोषणा जनवरी 2025 में इसी तरह के कदम के बाद की गई है, जब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से भी खुद को अलग कर लिया था, जो बहुपक्षीय वैश्विक निकायों से उसके चल रहे अलगाव को रेखांकित करता है।

BANKING & FINANCE

1. फेडरल बैंक ने ऑनलाइन कार्ड भुगतान के लिए भारत की पहली बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली शुरू की।



25 जुलाई 2025 को, फेडरल बैंक ने ई-कॉमर्स कार्ड लेनदेन के लिए भारत की पहली बायोमेट्रिक

प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करके डिजिटल भुगतान में एक अभूतपूर्व नवाचार पेश किया। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप, ऑनलाइन खरीदारी में लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना और धोखाधड़ी को कम करना है।

- फेडरल बैंक ई-कॉमर्स क्षेत्र में कार्ड-नॉट-प्रेजेंट (CNP) लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।

- यह प्रणाली ऑनलाइन कार्ड भुगतान को अधिकृत करने के लिए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स का उपयोग करती है, जो पारंपरिक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) आधारित प्रणालियों के लिए एक सहज और सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है।

- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डेटा सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे द्वारा संचालित है। यह आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रणाली का लाभ उठाती है और डिजिटल लेनदेन के दौरान डेटा चोरी और अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए कार्ड सत्यापन के दौरान एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करती है।

Key Points:-

(i) बैंक ने शुरुआत में प्रमुख महानगरों के चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा शुरू की है और अगली तिमाही में इसे पूरे देश में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ग्राहक इस सुविधा को फेडमोबाइल ऐप या अपनी नज़दीकी शाखा के माध्यम से वीज़ा और मास्टरकार्ड नेटवर्क के साथ सहजता से एकीकृत करके प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) बायोमेट्रिक ई-कॉमर्स सुरक्षा परियोजना, फेडरल बैंक की व्यापक डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है। यह सरकार के "डिजिटल इंडिया" मिशन के अनुरूप है और ग्राहकों के विश्वास और वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने वाले सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल नवाचारों का बीड़ा उठाकर

राष्ट्रीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है।

2. RBI ने जुलाई 2025 के प्रमुख निर्णयों में रेलिगेयर फिनवेस्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई योजना वापस ले ली और करवार अर्बन को-ऑप बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।



23 जुलाई, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दो प्रमुख नियामक घोषणाएं कीं - पहली, उसने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (REL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) पर लगाए गए सुधारात्मक कार्रवाई योजना (CAP) को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया, और दूसरी, उसने पूंजी और व्यवहार्यता मानदंडों का पालन न करने के कारण कर्नाटक के कारवार शहरी सहकारी बैंक (UCB) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।

- रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड पर सीएपी मूल रूप से 18 जनवरी, 2018 को लगाया गया था, क्योंकि 31 मार्च, 2017 को निरीक्षण के दौरान नियामक अनियमितताएं पाई गई थीं। इनमें बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी और वित्तीय मानदंडों का पालन न करना शामिल था।

- उस समय, NBFC ने मार्च 2022 तक 2,270 करोड़ रुपये का घाटा अर्जित किया था। हाल ही में सीएपी को वापस लेने के बावजूद, आरएफएल अभी भी

सभी लागू विवेकपूर्ण नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है।

• NBFC द्वारा महत्वपूर्ण वसूली उपाय किए गए, जिनमें मार्च 2023 में 16 ऋणदाताओं के साथ एकमुश्त समझौता भी शामिल है। इस समझौते के माध्यम से, RFL ने बैंकिंग प्रणाली को लगभग ₹9,000 करोड़ का भुगतान किया, जिसने RBI द्वारा CAP प्रतिबंध हटाने के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वित्तीय पुनर्गठन ने कंपनी के अनुपालन ट्रैक रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।

Key Points:-

(i) 2025 की शुरुआत में, बर्मन परिवार ने एक खुले प्रस्ताव के माध्यम से रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (REL) में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली। इस रणनीतिक अधिग्रहण ने बर्मन परिवार को प्रभावी रूप से आरईएल का प्रवर्तक बना दिया, जिससे उन्हें 25.16% शेयरधारिता प्राप्त हुई। उनके प्रवेश से आरएफएल के संचालन और शासन संरचना में दीर्घकालिक स्थिरता आने की उम्मीद है।

(ii) एक अलग घटनाक्रम में, RBI ने अपर्याप्त पूँजी पर्याप्तता और कमज़ोर आय संभावनाओं के कारण कर्नाटक के कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (UCBs) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और धारा 22(3)(d) के तहत की गई। यह रद्दीकरण 23 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा और बैंक को आगे कोई भी बैंकिंग गतिविधि करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(iii) RBI ने कर्नाटक सहकारी समिति रजिस्ट्रार (RoCS) से समापन प्रक्रिया शुरू करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। कारवार शहरी सहकारी बैंक के जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत ₹5 लाख तक के बीमा मुआवजे के पात्र हैं। यह कदम छोटे

जमाकर्ताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. प्रोफेसर उमा कांजीलाल को ऐतिहासिक रूप से पहली बार IGNOU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया।



इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने 25 जुलाई 2025 को प्रोफेसर उमा कांजीलाल को अपनी पहली महिला कुलपति नियुक्त करके इतिहास रच दिया। इस प्रतिष्ठित पद पर उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय की लगभग चार दशक की विरासत में एक मील का पत्थर है और मुक्त एवं डिजिटल शिक्षा में उनके गहन अनुभव को मान्यता प्रदान करती है।

• प्रोफेसर कांजीलाल मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) प्रणाली में 36 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवा का अनुभव रखती हैं। वे 1989 में IGNOU प्रशासन में शामिल हुईं और बाद में प्रो-वाइस-चांसलर (मार्च 2021-जुलाई 2024) और 25 जुलाई 2024 से कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य करते हुए, इस पूर्णकालिक नियुक्ति को प्राप्त किया।

• डिजिटल शिक्षा में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, उन्होंने इशू में कई शैक्षणिक और प्रशासनिक निकायों का नेतृत्व किया है, जिनमें

ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, प्रौद्योगिकी-सक्षम लचीली शिक्षा के लिए अंतर-विश्वविद्यालय संघ और सूचना विज्ञान एवं नवीन शिक्षण के लिए उन्नत केंद्र शामिल हैं। वे 2003 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की प्रोफेसर भी हैं।

Key Points:-

(i) राष्ट्रीय स्तर पर, वह शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहलों, SWAYAM and SWAYAM प्रभा के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करती हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और IGNOU में NMEICT चरण-III जैसी प्रमुख परियोजनाओं का संचालन किया है।

(ii) उनके अंतर्राष्ट्रीय योगदानों में UNRWA, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के लिए परामर्श और इलिनोइस विश्वविद्यालय में फुलब्राइट फेलोशिप शामिल हैं। उन्हें ई-शिक्षा के लिए मंथन पुरस्कार, ऑस्ट्रेलिया-भारत परिषद अनुदान और दानिडा फेलोशिप जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

(iii) IGNOU के कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति से दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, लचीली शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने और पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के IGNOU के मिशन को मजबूत करने की उम्मीद है।

2. निर्मल मिंडा को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ASSOCHAM का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।



जुलाई 2025 में, यूनो मिंडा लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

• इस नियुक्ति की घोषणा महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित ASSOCHAM की पहली प्रबंध समिति की बैठक के दौरान की गई। वह आगामी अध्यक्ष, सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष, संजय नायर के साथ मिलकर काम करेंगे।

• निर्मल मिंडा भारत के सबसे पुराने शीर्ष उद्योग मंडलों में से एक, एसोचैम में एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। उनकी नियुक्ति भारत के विनिर्माण और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में उनके दशकों पुराने योगदान को दर्शाती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, वे भारत में आर्थिक और व्यावसायिक विकास से संबंधित नीतिगत वकालत, औद्योगिक संवाद और रणनीतिक पहलों का समर्थन करेंगे।

• निर्मल मिंडा एक अनुभवी उद्योगपति हैं जिन्हें ऑटोमोटिव कंपोनेंट क्षेत्र में 50 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। वे वर्तमान में यूनो मिंडा (पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज) के प्रमुख हैं, जो दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है। उनके नेतृत्व में, कंपनी एक वैश्विक कंपनी के रूप में विकसित हुई है, जिसके दुनिया

भर में 73 कारखाने हैं और जिनके उत्पाद स्विचिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, ध्वनिक सिस्टम आदि जैसे उत्पादों से सुसज्जित हैं।

Key Points:-

(i) निर्मल मिंडा इससे पहले लगातार तीन वर्षों तक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके वैश्विक नेतृत्व ने ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में नीतियों और प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार देने में मदद की है, खासकर नवाचार और निर्यात क्षमता के क्षेत्र में। उनके कार्य ने गुणवत्तापूर्ण ऑटोमोटिव पार्ट्स के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ii) पिछले कुछ वर्षों में, निर्मल मिंडा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार मिले हैं। इनमें 2019 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर (मैनुफैक्चरिंग) पुरस्कार, उद्योग में उनके योगदान के लिए हरियाणा रत्न पुरस्कार और 2023 में प्रतिष्ठित हुरुन सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार शामिल हैं।

(iii) एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO अमिताभ चौधरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ASSOCHAM का उपाध्यक्ष (VP) भी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की अंतिम मंजूरी के अधीन है।

3. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने अर्थशास्त्री जस्टिन न्सेंगियुम्वा को नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया।



24 जुलाई 2025 को, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने डॉ. जस्टिन न्सेंगियुम्वा को रवांडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एडोर्ड एनगिरेंटे की जगह लेंगे, जो 2017 से इस पद पर थे। नियुक्ति की घोषणा रवांडा के सरकारी प्रवक्ता के कार्यालय के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सार्वजनिक रूप से की गई।

● जस्टिन न्सेंगियुम्वा, जो फरवरी 2025 से रवांडा के नेशनल बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, ने लीसेस्टर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की है और आर्थिक नीति और सार्वजनिक प्रशासन में दो दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

● केंद्रीय बैंक में शामिल होने से पहले, न्सेंगियुम्वा ने रवांडा के मंत्रालयों में वरिष्ठ सरकारी भूमिकाएं निभाई - उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और व्यापार और उद्योग मंत्रालय में स्थायी सचिव के रूप में कार्य किया, और देश के स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के परिवर्तन और आर्थिक नीति सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

● उनकी जीवनी का एक उल्लेखनीय पहलू 2008 में स्थायी सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का एक पुराना मामला है। राज्य मीडिया के अनुसार, बाद में उन्हें मार्च 2023 में राष्ट्रपति कागामे द्वारा 380 से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ क्षमा कर दिया गया था।

Key Points:-

(i) 2017 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत एनगिरेंटे ने एक्स पर अपना आभार व्यक्त करते हुए उनके कार्यकाल को "बेहद समृद्ध" बताया। रवांडा के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है, और 15 दिनों के भीतर नए मंत्रिमंडल का गठन अनिवार्य हो जाता है।

(ii) अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद, न्सेंगियुम्वा ने 23 जुलाई 2025 को ग्राम उरुग्विरो में राष्ट्रपति कागामे से मुलाकात की और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें रवांडा की राष्ट्रीय परिवर्तन रणनीति चरण 2 (NST2), विकास उद्देश्य और आगामी कार्यकाल के लिए शासन सुधार शामिल थे।

(iii) न्सेंगियुम्वा को NST2, रवांडा का पांच-वर्षीय सामाजिक-आर्थिक खाका (2024-2029) विरासत में मिला है, जिसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को 1,040 अमेरिकी डॉलर (2023) से बढ़ाकर 1,369 अमेरिकी डॉलर करना, निजी निवेश का विस्तार करना, 1.25 मिलियन नौकरियां पैदा करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और स्वच्छ जल, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है।

SPORTS

1. भारत ने FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।



भारत ने FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों 2025 में अपना पहला स्वर्ण पदक तब जीता जब तीरंदाज परनीत कौर और कुशल दलाल ने 26 जुलाई 2025 को जर्मनी के एस्सेन में मिश्रित कंपाउंड टीम का खिताब जीता। उनकी जीत ने विश्वविद्यालय स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया।

● एक रोमांचक फ़ाइनल में, परनीत और कुशल ने दक्षिण कोरिया को 157-154 के स्कोर से हराकर, हाफ़टाइम तक पिछड़ने के बाद नाटकीय वापसी की। उनके संयमित प्रदर्शन, जिसमें बाद के चरणों में लगातार "10" और "x" शॉट शामिल थे, ने दबाव में उनकी सटीकता को दर्शाया।

● इस स्वर्ण पदक के साथ ही उस दिन तीरंदाजी में भारत के कुल तीन पदक हो गए। मिश्रित टीम स्वर्ण के साथ, भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में रजत और महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इस स्पर्धा में अपनी गहरी पैठ का परिचय दिया।

Key Points:-

(i) राइन-रूहर क्षेत्र के एस्सेन जैसे शहरों में 16 से 27 जुलाई तक आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में 300 से ज़्यादा भारतीय एथलीटों ने 18 खेलों में भाग लिया। भारत पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा, जिसमें एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक शामिल

था।

(ii) एस्सेन में भारत का तीरंदाजी प्रदर्शन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर के खेल के बढ़ते कद को दर्शाता है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों और केंद्रित जमीनी स्तर की कोचिंग ने परनीत और कुशल जैसे तीरंदाजों की प्रतिभा को निखारा है, जिससे वैश्विक विश्वविद्यालय मंच पर भारत की प्रतिस्पर्धी उपस्थिति और भी मज़बूत हुई है।

2. भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर की CEO के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की, एथलीट एंटी-डोपिंग अनुशासन पैनल का गठन किया।



24 जुलाई, 2025 को, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की कार्यकारी परिषद (EC) ने रघुराम अय्यर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया और साथ ही एथलीट एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल (AADDP) की स्थापना की। इन निर्णयों का उद्देश्य वैश्विक खेल प्राधिकरणों की बढ़ती निगरानी के बीच प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार और डोपिंग से निपटना है।

● रघुराम अय्यर की नियुक्ति IOA के संचालन और अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधी मानदंडों के अनुपालन को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की बढ़ती आलोचना के बाद हुई है। यह निर्णय IOA के आंतरिक ढांचे को मज़बूत करता है और भारत के

खेल प्रशासन से संबंधित वैश्विक चिंताओं को दूर करने का लक्ष्य रखता है।

● रघुराम अय्यर एक विविध नेतृत्व अनुभव लेकर आए हैं, और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और डिस्कवरी चैनल में कार्यकारी पदों पर कार्य कर चुके हैं। 2007 में, वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रैंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स में CEO के रूप में शामिल हुए और बाद में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स (RPSG), लखनऊ सुपरजाइंट्स (LSG), एटीके मोहन बागान और UAT की RPSG मावेरेक्स सहित कई खेल फ्रैंचाइज़ी के साथ काम किया।

● अय्यर को 2024 के लिए एक उच्च-स्तरीय नामांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया था, जिसमें पी.टी. उषा (अध्यक्ष, IOA), मैरी कॉम (एथलीट आयोग की अध्यक्ष) और नीता अंबानी (भारत से IOC सदस्य) शामिल थीं। उनकी नियुक्ति को IOA के प्रशासनिक नेतृत्व के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Key Points:-

(i) नवगठित एथलीट एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल (AADDP) डोपिंग उल्लंघनों से जुड़ी बढ़ती चिंताओं का समाधान करेगा। इस पैनल का नेतृत्व पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल करेंगे और इसमें डॉ. पीएसएम चंद्रन (खेल चिकित्सा), अपर्णा पोपट (बैडमिंटन), डॉ. अनिघ चौधरी (कानूनी विशेषज्ञ), मेजर जनरल दिलावर सिंह (खेल प्रशासन), और डॉ. सुधीर के. जैन (स्वास्थ्य विज्ञान) जैसे प्रमुख सदस्य शामिल हैं।

(ii) AADDP की मुख्य भूमिका डोपिंग से संबंधित मामलों में पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करना और एथलीटों, प्रशिक्षकों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। यह पैनल विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) और भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) द्वारा निर्धारित वैश्विक डोपिंग रोधी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(iii) भारत के डोपिंग रोधी प्रयासों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, खासकर 2023 में 3.8% डोपिंग पॉजिटिविटी दर दर्ज होने के बाद। AADDP की स्थापना स्वच्छ खेल को बनाए रखने और भारत की वैश्विक खेल प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए IOA की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

AWARDS

1. ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान के लिए जी.पी. बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



25 जुलाई 2025 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन को हैदराबाद में प्रतिष्ठित जी.पी. बिड़ला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी.पी. बिड़ला पुरातत्व, खगोलीय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष निर्मला बिड़ला द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार भारत के क्रायोजेनिक और अंतरिक्ष अभियानों को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व को सम्मानित करता है।

• डॉ. नारायणन ने 13 जनवरी 2025 को ISRO के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे डॉ. एस. सोमनाथ के उत्तराधिकारी होंगे। इसरो में चार दशकों से अधिक

समय तक कार्यरत रहने वाले एक अनुभवी प्रणोदन विशेषज्ञ, डॉ. नारायणन की विशेषज्ञता क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग और रॉकेट प्रौद्योगिकी में है।

• IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र, डॉ. नारायणन ने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एम.टेक और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की उपाधि प्राप्त की है। इससे पहले, उन्होंने 2018 से 2025 तक ISRO के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) के निदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और गगनयान जैसे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रणोदन प्रणालियों के विकास का नेतृत्व किया।

Key Points:-

(i) जी.पी. बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार, जिसे पहले लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दिया जाता है जिनके कार्यों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पूर्व प्राप्तकर्ताओं में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. वेंकटरमन रामकृष्णन, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन जैसी उल्लेखनीय हस्तियाँ शामिल हैं।

(ii) हैदराबाद में आयोजित समारोह के दौरान, डॉ. नारायणन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर जी.पी. बिड़ला स्मृति व्याख्यान दिया। उन्होंने तीन वर्षों के भीतर कक्षा में उपग्रहों की संख्या लगभग तिगुनी करने—लगभग 55 से 150 से अधिक—के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ISRO की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि की।

(iii) यह मान्यता अंतरिक्ष अन्वेषण और नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करती है। डॉ. नारायणन के नेतृत्व में, इसरो NASA - ISRO NISAR जैसे मिशनों को अंजाम देने, गगनयान की परीक्षण उड़ानों को पूरा करने और 2028 तक भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल और 2035 तक एक पूर्ण विकसित स्टेशन का मार्ग प्रशस्त करने की

योजना बना रहा है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई 2025 को मनाया गया।



विश्व मैंग्रोव दिवस—जिसे आधिकारिक तौर पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है—हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। UNESCO द्वारा 2015 में स्थापित, इस दिवस को पहली बार जुलाई 2016 में मैंग्रोव वनों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया था।

- 6 नवंबर 2015 को पेरिस में यूनेस्को के 38वें आम सम्मेलन के दौरान, इक्वाडोर के अनुरोध के बाद प्रस्ताव 38सी/66 के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई।

- 26 जुलाई की तारीख, दिवंगत ग्रीनपीस कार्यकर्ता हेहाउ डैनियल नैनोटो की स्मृति में मनाई जाती है, जिनकी मृत्यु 1998 में इसी दिन इक्वाडोर में मैंग्रोव आर्द्रभूमि की बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन करते समय हुई थी।

- मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित दुर्लभ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जहाँ भूमि समुद्र से मिलती है। वैश्विक उष्णकटिबंधीय

वनों के 1% से भी कम क्षेत्र में फैले होने के बावजूद, ये जैव विविधता के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, तटरेखाओं को तूफानों और कटाव से बचाते हैं, और कई भूमि-आधारित पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में पाँच गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Key Points:-

(i) पिछले चार दशकों में, वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव क्षेत्र में लगभग 50% की गिरावट आई है, और कुछ देशों में 1980 और 2005 के बीच 40% से भी अधिक की कमी आई है। तटीय विकास, झींगा पालन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे त्वरित खतरों ने इनके विनाश को और तीव्र कर दिया है। यह दिवस मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

(ii) जहाँ UNESCO वैश्विक जागरूकता और संरक्षण का नेतृत्व करता है, वहीं राष्ट्रीय पहल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की मिष्टी (तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल) योजना के तहत, गुजरात ने 2025 में मैंग्रोव की खेती में अग्रणी भूमिका निभाई और कच्छ जिले में 6,000 हेक्टेयर सहित 19,520 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्स्थापित किया। भारत का कुल मैंग्रोव क्षेत्र लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें सुंदरबन क्षेत्र दुनिया के सबसे सघन मैंग्रोव आवासों में से एक है।

2. विश्व डूबने से बचाव दिवस 2025 विश्व स्तर पर 25 जुलाई को मनाया गया।



25 जुलाई, 2025 को, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने डूबने के खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने, जीवन रक्षक पहलों का समर्थन करने और जल-संबंधी मौतों को रोकने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई को उत्प्रेरित करने के लिए दुनिया भर में विश्व डूबने से बचाव दिवस का 5वां संस्करण मनाया।

- यह दिन बेहतर जल सुरक्षा शिक्षा, जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षण और मजबूत नीतियों के माध्यम से डूबने से होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रयास का आह्वान करता है।

- 2025 का विषय था "आपकी कहानी एक जीवन बचा सकती है।", जिसमें उत्तरजीवी कहानियों, सुरक्षा जागरूकता और जीवन बचाने में साझा अनुभवों के महत्व पर जोर दिया गया।

- विश्व डूबने से बचाव दिवस पहली बार 25 जुलाई 2021 को मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 28 अप्रैल 2021 (A/RES/75/273) को एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें डूबने से उत्पन्न वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी।

Key Points:-

(i) 2025 के इस आयोजन में सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और वैश्विक साझेदारों की व्यापक भागीदारी

रही। यह पहल मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में पारित "वैश्विक स्तर पर डूबने की रोकथाम के लिए कार्रवाई में तेज़ी" प्रस्ताव के अनुरूप है। यह जल सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए मजबूत और निरंतर वैश्विक साझेदारियों का आह्वान करता है।

(ii) यह प्रस्ताव बांग्लादेश और आयरलैंड द्वारा सह-प्रायोजित था, जिसे 72 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, तथा इसमें हितधारकों से डूबने की रोकथाम को प्राथमिकता देने और 2029 तक कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया।

(iii) यह सहयोग दुनिया भर में असुरक्षित समुदायों में अपरिहार्य मौतों को रोकने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए जारी है।

3. विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) दिवस 2025 विश्व स्तर पर 25 जुलाई को मनाया गया।



विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) दिवस, जिसे विश्व भ्रूणविज्ञानी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 25 जुलाई 2025 को विश्व स्तर पर IVF तकनीक और सहायक प्रजनन तकनीक (ART) के माध्यम से बांझपन के इलाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। यह दिन

चिकित्सा इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाता है जिसने प्रजनन विज्ञान को बदल दिया।

● यह दिन लुईस ब्राउन के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो आईवीएफ तकनीक से गर्भ धारण करने वाली दुनिया की पहली बच्ची थीं। 25 जुलाई 1978 को यूनाइटेड किंगडम में जन्मी, उनके जन्म ने बांझ दंपतियों की मदद के लिए वर्षों से किए जा रहे चिकित्सा प्रयोगों की सफलता को चिह्नित किया।

Key Points:-

- (i) पहली सफल IVF प्रक्रिया डॉ. पैट्रिक क्रिस्टोफर स्टेप्टो, डॉ. रॉबर्ट जेफ्री एडवर्ड्स और जीन मैरियन पर्डी के अग्रणी प्रयासों के कारण UK में संपन्न हुई।
- (ii) डॉ. केरशॉ कॉटेज अस्पताल में उनके समन्वित कार्य ने लेस्ली ब्राउन को 100 से अधिक असफल भ्रूण स्थानांतरण प्रयासों के बाद अपनी बेटी लुईस को गर्भ धारण करने में मदद की।
- (iii) इन योगदानों के सम्मान में, "IVF के जनक" के रूप में विख्यात डॉ. रॉबर्ट एडवर्ड्स को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के विकास में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2010 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज, IVF ने दुनिया भर में लाखों परिवारों को आशा की किरण दिखाई है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO ने आंध्र प्रदेश में उन्नत UAV-लॉन्च मिसाइल ULPGM-V3 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।



जुलाई 2025 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आंध्र प्रदेश (AP) के कुरनूल ज़िले में स्थित राष्ट्रीय मुक्त वायु रेंज (NOAR) में उन्नत मानवरहित हवाई वाहन (UAV)-प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल (ULPGM)-V3 के सफल उड़ान परीक्षण किए। यह उन्नत मिसाइल अगली पीढ़ी का एक संस्करण है जिसे कम संपार्श्विक क्षति के साथ सटीक प्रहार के लिए डिज़ाइन किया गया है।

● ULPGM-V3 एक दागो और भूल जाओ, सटीक मार्गदर्शन वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे UAV प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से स्थिर और गतिशील, दोनों तरह के दुश्मन लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है, साथ ही कर्मियों के लिए परिचालन जोखिम को कम से कम करने के लिए भी।

● यह संस्करण पिछले ULPGM-V2 पर आधारित है, जिसे मूल रूप से DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) द्वारा विकसित किया गया था, और इसमें बेहतर सटीकता, लक्ष्यीकरण और नियंत्रण प्रणाली की सुविधा है।

● ULPGM-V3 के विकास में DRDO और भारतीय रक्षा उद्योग के दिग्गजों, जिनमें विकास-सह-उत्पादन साझेदार (DcPPs), MSMEs और स्वदेशी स्टार्ट-अप शामिल हैं, के बीच एक मज़बूत साझेदारी शामिल है। इस मिसाइल का निर्माण भारत

डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने अदानी डिफेंस सिस्टम्स के सहयोग से किया है, जो भारत में सार्वजनिक-निजी रक्षा पहलों की सफलता को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) तकनीकी रूप से, ULPGM-V3 का वज़न 12.5 किलोग्राम है और इसमें दोहरे-प्रणोद वाले ठोस प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो दिन के उजाले में 4 किमी और रात में 2.5 किमी तक के दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह कम रोशनी में भी सटीक मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर तकनीक का इस्तेमाल करता है और इसमें विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (ERA) वाले कवच को ध्वस्त करने के लिए अनुकूलित टैंडम वारहेड्स लगे हैं।

(ii) मिसाइल की उन्नत विशेषताओं में दो-तरफ़ा संचार लिंक, उन्नत इमेजिंग सिस्टम और मिशन मापदंडों में वास्तविक समय में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए एआई-सक्षम निर्णय समर्थन शामिल हैं।

(iii) ULPGM-V3 कई UAV प्लेटफार्मों के साथ संगत है और भारत के रक्षा बलों को विविध इलाकों और खतरे वाले वातावरण में सटीक हमला मिशनों के लिए बहुमुखी और स्वदेशी समाधान प्रदान करता है।

2. IDEF 2025 में तुर्की ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल "तयफुन ब्लॉक-4" का अनावरण किया।



जुलाई 2025 में, तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले (IDEF 2025) के दौरान अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल "तयफुन ब्लॉक-4" का अनावरण किया। यह लॉन्च तुर्की के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाना और अपने सैन्य प्रतिरोध को मजबूत करना है।

● तयफुन ब्लॉक-4 के लॉन्च के साथ, तुर्की संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा NATO (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) सदस्य बन गया है जिसने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। यह उपलब्धि तुर्की को अमेरिका, रूस और चीन जैसे वैश्विक हाइपरसोनिक शक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है।

● इस मिसाइल को प्रमुख तुर्की रक्षा निर्माता रोकसेटन (Roketsan) द्वारा विकसित किया गया है। तयफुन ब्लॉक-4 एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Mach 5 (आवाज़ की गति से 5 गुना) से अधिक की रफ़्तार प्राप्त कर सकती है और उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है।

● इस मिसाइल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GLONASS) और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS)

को एकीकृत किया गया है, जिससे यह अत्यधिक सटीक बनती है। यह प्रणाली सिर्फ 5 मीटर की अधिकतम त्रुटि सीमा के साथ लक्ष्य को भेद सकती है।

Key Points:-

(i) तकनीकी विशिष्टताओं की बात करें तो तयफुन ब्लॉक-4 की लंबाई 6.5 मीटर, व्यास 938 मिमी, और कुल वजन 2,300 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 800 किलोमीटर है और इसमें मल्टी-पर्पज वॉरहेड का इस्तेमाल होता है। इसे मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर (MTEL) से लॉन्च किया जाता है, जो इसे कठिन इलाकों में भी तैनात करने योग्य बनाता है।

(ii) तयफुन ब्लॉक-4 के इस अनावरण के साथ, तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और यह दिखाया है कि वह अगली पीढ़ी के हथियारों के विकास में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

Static GK

Central Board of Direct Taxes (CBDT)	वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण	मुख्यालय: नई दिल्ली
Universal Postal Union (UPU)	महानिदेशक (DG) : मासाहिको मेटोकी	मुख्यालय : बर्न, स्विट्ज़रलैंड
Maldives	अध्यक्ष: मोहम्मद मुइज़्ज़ू	राजधानी: माले
Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	मुख्यालय : नई दिल्ली	स्थापना : 1920
DRDO	अध्यक्ष: डॉ. समीर वेंकटपति कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	महानिदेशक (DG) : ऑट्टो अज़ोले	मुख्यालय पेरिस, फ़्रांस
Federal Bank	CEO : KVS मणियन	मुख्यालय: अलुवा
Rwanda	राष्ट्रपति : पॉल कागामे	राजधानी : किगाली

Religare Enterprises Limited (REL)	अंतरिम अध्यक्ष : प्रवीण कुमार त्रिपाठी	मुख्यालय: नई दिल्ली
ISRO	अध्यक्ष: वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु